

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एस.एस. सविहावालिया, और माननीय न्यायमूर्ति हरबंस लाल, के समक्ष

डेस राज जुनेजा और अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाता।

1977 की सिविल रिट याचिका संख्या 3958

19 फरवरी, 1979।

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम (1952 का XXVII) जैसा कि पंजाब अधिनियम (1957 का XXXVII) द्वारा संशोधित किया गया है - धारा 7, 7A और दूसरी अनुसूची - पंजाब नगरपालिका अधिनियम (1911 का III) - धारा 4, 11, 51, 52, 61 से 84 - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 141 आश्वासन सरकार द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए कोई कर नहीं लगाना - उत्तराधिकारी सरकार - क्या उस अवधि की समाप्ति से पहले गृह कर लगाने से रोक दिया गया है - वचन का सिद्धांत मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचनाओं के आधार पर गृह कर लगाने का निर्णय - धारा सहित ऐसी अधिसूचनाएं 61 और नगरपालिका अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों को दूसरी अनुसूची में शामिल करना और उन्हें चंडीगढ़ में लागू करना - चाहे विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण प्रभावित हो - मुख्य आयुक्त विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हो - चाहे विधायी कार्य करता हो - एक 'नगर पालिका' और 'नगरपालिका निधि' का गठन - क्या गृह कर लगाने से पहले आवश्यक पूर्व-शर्त - उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बीच संघर्ष - किन निर्णयों को कानून की घोषणा के रूप में लिया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया की केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन चंडीगढ़ ने हाउस टैक्स लगाने का फैसला करते हुए और पंजाब-नगरपालिका अधिनियम 1911 की धारा 61 और अन्य प्रावधानों को पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम 1952 की दूसरी अनुसूची में शामिल करते हुए विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में विधायी कार्यों का प्रयोग किया। ऐसा होने के कारण, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि नहीं! चंडीगढ़ में एक विशिष्ट अवधि के लिए लगाया जाने वाला कर किसी अन्य प्रकार के वचन पत्र के रूप में काम नहीं कर सकता है क्योंकि विधायिका एक संप्रभु निकाय है और इसे भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 265 के तहत कानून के संबंध में संप्रभु शक्तियों के साथ निवेश किया गया है। विधायी कार्यों का अभ्यास करते समय इसके प्रतिनिधि भी उस चरित्र में भाग लेते हैं। यदि किसी भी शर्त को बाध्यकारी माना जाता है तो यह विधायिका को गृह कर के संबंध में एक निश्चित कानून पारित नहीं करने के अधिदेश की प्रकृति में होगा जो किया नहीं जा सकता है। यह निर्विवाद है कि, विधायिका के कानून के खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रत्यायोजित प्राधिकारी, जो गृह कर लगाने की अधिसूचना जारी करने में विधायिका की शक्ति का प्रयोग करने वाला मुख्य आयुक्त था, वचन पत्र के सिद्धांत के आधार पर हमले से मुक्त था। पिछली सरकार द्वारा > विशिष्ट अवधि के लिए चंडीगढ़ शहर में भूमि और भवनों पर गृह कर सहित कोई कर न लगाने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उस अवधि की समाप्ति से पहले गृह कर लगाने से वचन पत्र के सिद्धांत के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया था। (पैरा 17)।

यह अभिनिर्धारित किया गया की सरकार या कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन हमारे देश सहित सभी लोकतांत्रिक देशों में सभी विधायिकाओं की स्वीकृत नीति है, लेकिन इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को वैध होने के लिए, केवल निर्दिष्ट क्षेत्र की चार दीवारों के भीतर काम करना चाहिए। विधायिका को किसी विशेष अधिनियमन में नीति, सिद्धांत या मानक को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और अस्पष्टता के लिए कोई गुंजाइश छोड़े बिना और पर्याप्त दिशा-निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए। अंदर रहते हुए कराधान के क्षेत्र में भी, शक्ति का प्रत्यायोजन स्वीकार्य है, लेकिन किसी विशेष कर को लागू करने के लिए विधायिका के मन को कानून में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'नीतिगत मामले के रूप में कर लगाने को कार्यपालिका की दया और मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता।' <sup>^</sup> ईआर ० कर लोगों की संप्रभुता की एक अनिवार्य विशेषता है जिसे संविधान के तहत विधायिका में निहित किया गया है। यदि विधायिका सिद्धांत या नीति के रूप में स्पष्ट रूप से एक निश्चित कर लगाने का निर्णय लेती है, तो कर की दरें, इसे लगाने का तरीका और यहां तक कि जिन व्यक्तियों पर बोझ होना चाहिए, उन्हें भी निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कार्यपालिका को सौंप दिया जा सकता है। तथापि, इस प्रकार कर लगाने का निर्णय प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। ऐसी आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन समान होगा; आवश्यक विधायी, कार्यों का त्याग करना। नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 में विधायिका की (भवनों आदि के मालिकों पर) कर लगाने या दूसरे शब्दों में गृह कर लगाने की नीति सन्निहित है। अगर विधायिका ने अपना मन बना लिया होता; 1957 के संशोधन अधिनियम को लागू करते समय कि हाउस टैक्स लगाया जाना चाहिए और केवल विवरण कार्यपालिका पर छोड़ा जाना चाहिए, कुछ भी रास्ते में नहीं आया। नगरपालिका अधिनियम की कम से कम धारा 61 और 62 को दूसरी अनुसूची में शामिल करके अपनी इच्छा और इरादे को व्यक्त करने में विधायिका का गठन। कर से संबंधित इन दो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल न करने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि तत्कालीन विधायिका ने चंडीगढ़ में गृह कर लगाने के संबंध में वांछनीयता या उपयुक्तता के लिए अपना दिमाग नहीं लगाया था जो एक नया विकासशील शहर था। केवल यह तथ्य कि राज्य सरकार को प्रधान अधिनियम की धारा 7ए के तहत और पुनर्गठन के बाद मुख्य आयुक्त को नगरपालिका अधिनियम के किसी भी प्रावधान को दूसरी

अनुसूची में शामिल करने की शक्ति दी गई थी, को विधायिका द्वारा स्पष्ट शब्दों में इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जा सकता है कि वह चाहती थी कि चंडीगढ़ में हाउस टैक्स लगाया जाए। नीति निर्धारित करने के मामले में, ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है जिसकी अनुमति नहीं है (विधायिका के साथ कानून की संप्रभु शक्ति की जड़ में कटौती)। कर लगाने से संबंधित प्रावधान और इसे लगाने के तरीके और तंत्र सहित दूसरी अनुसूची में धारा 7-क के अंतर्गत नगरपालिका अधिनियम के किसी भी प्रावधान को शामिल करना सरकार के असीमित और निरंकुश विवेक पर छोड़ दिया गया था। इस तरह की व्यापक शक्तियों के प्रत्यायोजन और इसका प्रयोग; इसे "सशर्त कानून" के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। मुख्य आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना जिसके तहत चंडीगढ़ में हाउस टैक्स लगाने से संबंधित नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 और अन्य प्रावधान दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था जो स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह एसेन के अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल के विकार से ग्रस्त है विधायी कार्य।

(पैरा 36, 37, 38 और 40)

यह अभिनिर्धारित किया गया की नगरपालिका अधिनियम की योजना के अनुसार, नगरपालिका 1 समिति चाहे नामित हो या निर्वाचित, अधिनियम की धारा 4 के तहत विधिवत गठित नगरपालिका के अस्तित्व का अनुमान लगाती है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 4, 51, [52 और 61 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों) को प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। [योजना के अनुसार] टैक्स या अन्यथा से प्राप्त सभी आय और राजस्व को [नगरपालिका में] जमा किया जाना है। ऐसी निधि जिसका गठन संबंधित नगरपालिका के नाम पर किया जाना हो। कानूनी इकाई (जिसे नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 के तहत विचार ति 'नगरपालिका' के रूप में जाना जाता है) के अस्तित्व में आए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत परिकल्पित कोई नगरपालिका निधि नहीं हो सकती है क्योंकि निधि नगरपालिका के नाम पर होनी चाहिए और इसका उपयोग उद्देश्यों के लिए और स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। नीचे नगरपालिका अधिनियम की धारा 52 नगरपालिका और उसके लिए नगरपालिका निधि की अनुपस्थिति में कर का उपयोग करने के लिए मशीनरी जो [धारा 61 और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत लगाया और एकत्र किया जा सकता है] पूरी तरह से कमी होगी और यह नहीं कहा जा सकता है कि कर 'इस (नगरपालिका) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए' लगाया गया है। इस प्रकार, नगरपालिका को अस्तित्व में लाए बिना नगरपालिका निधि नहीं बनाई जा सकती थी और नगरपालिका निधि के गठन के बिना, नगरपालिका कर की लेवी नगरपालिका के रूप में प्रभावी नहीं हो सकती थी। और गृह कर लगाने से पहले नगरपालिका निधि आवश्यक पूर्व शर्त थीं क्योंकि अन्यथा, अधिनियम का उद्देश्य और अधिनियम की धारा 61 के तहत परिकल्पित तरीके को पूरा नहीं किया जा सकता था।

(पैरा 41)।

यह अभिनिर्धारित किया गया की ऐसे मामलों में जहां उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बीच कोई टकराव दिखाई देता है, उसे छोटी पीठों द्वारा व्यक्त की गई राय के बजाय बड़ी पीठों द्वारा व्यक्त की गई राय का पता लगाने और उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, हालांकि बाद की राय बाद में हो सकती है। इसलिए, वृहद पीठ का निर्णय उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इसकी परिकल्पना की गई है।

(पैरा 14 और 15)।

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित जारी करने की कृपा करें: -*

- I. आक्षेपित अधिसूचनाओं को रद्द करने वाली सर्विओररी रिट आगे समामेलन पी -1, पी -5, पी -6, पी -7, पी -8, पी -9, पी -10, पी -11 और पी -13; में
- II. परमादेश की एक रिट जिसमें यह घोषणा की गई हो कि आक्षेपित आदेश और आदेश अमान्य, अमान्य, क्षेत्राधिकार से परे और असंवैधानिक हैं;
- III. कि कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे।
- IV. परमादेश की एक रिट में यह घोषणा की गई है कि चंडीगढ़ में वर्ष 1984 तक कोई गृह कर नहीं लगाया जा सकता है।

उत्तरदाताओं को उस समय तक चंडीगढ़ में पंजाब नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से रोक दिया जाता है।

- V. परमादेश की एक रिट में यह घोषणा की गई है कि अधिसूचनाएं- अनुलग्नक पी-5, पी-6 के तहत अमान्य हैं, [कानून का कोई बल नहीं है और पी-1 का कोई प्रभाव नहीं है।
- VI. परमादेश की एक रिट जिसमें यह घोषणा की गई हो कि धारा 12 पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 जहां तक यह चंडीगढ़ पर लागू है, असंवैधानिक और शून्य है;
- VII. परमादेश की एक रिट में यह घोषणा की गई है कि 1959 में पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के निर्णय को

उत्तरवर्ती राज्य प्रतिवादी संख्या 1000 द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है। 1 और उन पर बाध्यकारी है और वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू होता है और प्रतिवादी अभ्यावेदनों से बंधे होते हैं [पूर्ववर्ती राज्य द्वारा किए गए और उत्तराधिकारी इसे वापस लेने के लिए सक्षम नहीं है;

VIII. इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

IX. प्रस्ताव की सूचना की सर्विसिंग समाप्त की जाए;

*यह भी अनुरोध किया जाता है कि जब तक रिट याचिका पर निर्णय नहीं आ जाता, तब तक लागू आदेशों के संचालन और आकलन प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल, उनके साथ बी. एस. मलिक, एस. सी. सिब्बल, आर. सी. सेतिया, ए. के. जायसवाल, जे. एस. चावला और आर. एन. नरूला, अधिवक्ता हैं।

प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट एम एल बंसल के साथ संयुक्त अधिवक्ता आनंद स्वरूप।

## निर्णय

मन्त्रानीय न्यायमूर्ति हरबंस लाल

1. यह आदेश 1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 7218, 1977 की 519, 2538, 3880 और 3958 और 1978 की 319, 1046, 1241, 1577 और 4733 का निपटारा करेगा, क्योंकि इसमें उठने वाले कानून और तथ्य के अधिकांश प्रश्न समान हैं।

2. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ द्वारा 1 अक्टूबर, 1976 से हाउस टैक्स लगाया गया था। वैधता देस राज जुनेजा और अन्य *बहुत*/ भारत संघ और अन्य (हरबंस लाल, जे)

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इन सभी रिट याचिकाओं में मुख्य रूप से कानून के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के आधार पर इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया है:

- I. तत्कालीन पंजाब सरकार, जिसका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उत्तराधिकारी है, ने 1966 में पुनर्गठन के बाद 1959 में आश्वासन दिया था कि 25 वर्षों तक चंडीगढ़ शहर में हाउस टैक्स सहित कोई कर नहीं लगाया जाएगा। नतीजतन, चंडीगढ़ प्रशासन को वचन पत्र के सिद्धांत के तहत हाउस टैक्स लगाने से रोक दिया गया था, और
- II. हाउस टैक्स लगाने का निर्णय मुख्य आयुक्त और मुख्य प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की अधिसूचनाओं पर आधारित था, जो विधायी शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण प्रभावित हुए थे।

3. इस स्तर पर, 1977 की सिविल रिट याचिका संख्या 3958 में उल्लिखित प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में गिनाना उचित है, जिनका विवाद पर असर पड़ता है।

4. ऐतिहासिक प्रलय और 1947 में देश के परिणामी विभाजन के परिणामस्वरूप, पंजाब की राजधानी लाहौर को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया था और पंजाब का शेष हिस्सा, जिसे पूर्वी पंजाब के रूप में जाना जाता था, बिना किसी राजधानी के छोड़ दिया गया था। दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को पूरा करने के लिए, नए पंजाब राज्य के सभी प्रमुख कार्यालयों को पहले शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। उच्चतम स्तर पर अच्छी चर्चा के बाद, आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि इसकी नई राजधानी उस स्थान पर स्थापित की जाए जिसे अब चंडीगढ़ कहा जाता है। 1952 में, पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम संख्या XXVII) (इसके बाद प्रधान अधिनियम कहा जाता है) को प्रख्यापित किया गया था। इसका उद्देश्य था, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट है, निम्नानुसार है:-

उन्होंने कहा, "चंडीगढ़ में पंजाब की नई राजधानी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह आवश्यक समझा जाता है कि राज्य सरकार को भवन स्थलों की बिक्री को विनियमित करने और नगरपालिका उप-नियमों की तर्ज पर भवन निर्माण नियमों को लागू करने के लिए कानूनी अधिकार दिया जाए, जब तक कि उचित रूप से गठित स्थानीय निकाय शहर के प्रशासन को अपने हाथ में नहीं ले लेता।

इस अधिनियम की धारा 7 के तहत, राज्य सरकार को ऐसे शुल्क या कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था जो चंडीगढ़ में किसी भी सुविधा को प्रदान करने, बनाए रखने और जारी रखने के लिए आवश्यक हो। इस अधिनियम को 1957 के पंजाब अधिनियम संख्या 37 द्वारा संशोधित किया गया था; पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1957 (इसके बाद संशोधन अधिनियम कहा जाता है), जिसे प्राप्त किया गया! 11 नवंबर, 1957 को राज्यपाल की सहमति। संशोधन अधिनियम की घोषणा के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, संशोधन का उद्देश्य "चंडीगढ़ में मुख्य प्रशासक को 1911 के नगरपालिका अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों में निहित शक्तियों के समान शक्तियां देना था, जिसका उपयोग वह चंडीगढ़ के राजधानी क्षेत्र के भीतर करेंगे। धारा 7-ए को संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- I. "7-ए (एल) मुख्य प्रशासक, समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और राज्य

सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से में ऐसे अनुकूलन और संशोधनों के साथ लागू कर सकता है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट पदार्थ को प्रभावित नहीं करते हैं, पंजाब नगरपालिका अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान <sup>^</sup> (ग) इस अधिनियम में संलग्न दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 1911 को इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न होने तक विनिर्दिष्ट किया गया है।

- II. उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, मुख्य प्रशासक, चंडीगढ़ या उसके किसी भाग के संबंध में, जैसा भी मामला हो, उसका प्रयोग करेगा; ऐसी अधिसूचना द्वारा लागू प्रावधानों के तहत वही कार्य करने और नियंत्रण और नियंत्रण करना जो नगरपालिका समिति या उसके अध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी या समिति का कोई अन्य पदाधिकारी प्रयोग करेगा और प्रदर्शन करेगा; यदि चंडीगढ़ प्रथम श्रेणी की नगर पालिका थी।
- III. शक्तियों का प्रयोग करते समय या कार्यों का पालन करते समय पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के प्रावधानों के तहत, उप-धारा के तहत एक अधिसूचना द्वारा चंडीगढ़ पर लागू किया गया आर (1), मुख्य प्रशासक नियंत्रण के अधीन होगा . राज्य सरकार का न कि आयुक्त या उपायुक्त का।
- IV. राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के किसी प्रावधान को हटा सकती है। पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911, दूसरी अनुसूची से या उसमें उस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को जोड़ना।
- V. उपधारा (1) के तहत की गई प्रत्येक अधिसूचना को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जल्द से जल्द चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा।

इस अधिनियम के साथ संलग्न दूसरी अनुसूची में, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (इसके बाद नगरपालिका अधिनियम कहा जाता है) के कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया था। धारा 7-ए और अनुसूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दूसरी अनुसूची में शामिल नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ प्रशासक द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में लागू किया जा सकता है। जिन अन्य प्रावधानों का दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है, उन्हें केवल तभी लागू किया जा सकता है जब राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा उन्हें दूसरी अनुसूची में शामिल करे। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 से 84 . गृहकर लगाने और इसे लगाने के तरीके और विधि से संबंधित को संशोधन अधिनियम के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। 10 जुलाई, 1968 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने प्रिंसिपल एक्ट की धारा 7-ए (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें नगरपालिका अधिनियम की धारा 61, 62, 63, 81, 84 और 85 को दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया। 31 जुलाई, 1968 को इन नए प्रावधानों को 31 जुलाई, 1968 की अधिसूचना के माध्यम से मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ चंडीगढ़ में लागू किया गया था।

5. प्रधान अधिनियम की धारा 7-ए की उप-धारा (5) के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिनों की अवधि के लिए जल्द से जल्द रखा जाना आवश्यक था। गृहकर लगाने को अधिकृत करने वाले नगरपालिका अधिनियम के कुछ प्रावधानों को शामिल करने से संबंधित 10 जुलाई, 1968 और 31 जुलाई, 1968 की उपर्युक्त दो अधिसूचनाएं राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखी गई थीं।

6. देश के विभाजन के बाद, स्वतंत्र भारत में विभिन्न प्रांतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जहां तक तत्कालीन पूर्वी पंजाब से सटी रियासतों का संबंध था, उन्हें पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के नाम से जाना जाने वाला एक अलग संघ में एकीकृत किया गया था

(PEPSU) 1951 में। इसके बाद, उन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के माध्यम से पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। इसके बाद, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (इसके बाद पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है) द्वारा 1966 में पंजाब के नए एकीकृत प्रांत को फिर से तीन अलग-अलग प्रांतों में पुनर्गठित किया गया, जिन्हें पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के रूप में जाना जाता है। जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासित संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का संबंध था, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 में केन्द्र सरकार को नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से पहले तत्कालीन पंजाब में विद्यमान कानूनों के ऐसे अनुकूलन और संशोधन करने की शक्ति निहित थी। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन (चंडीगढ़) (राज्यों और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1968 (इसके बाद आदेश कहा जाता है) के रूप में जाना जाने वाला एक अधिसूचना जारी की, जिसके माध्यम से, धारा 7-ए की उपधारा (5) को हटाते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रिंसिपल एक्ट और संशोधन अधिनियम लागू किए गए। जिसके लिए धारा 7-ए की उप-धारा (1) के तहत सभी अधिसूचनाओं को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक था। जाहिर है, इस अनुकूलन का उद्देश्य केंद्र सरकार को राज्य विधानमंडल के समक्ष किसी भी अधिसूचना को रखने की जिम्मेदारी से मुक्त करना था, जो कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके उत्तराधिकारी, संसद के संबंध में मौजूद नहीं था।

7. मई, 1959 में, पंजाब की तत्कालीन सरकार ने मंत्रिमंडल की एक बैठक में चंडीगढ़ के नागरिकों को आश्वासन देते हुए निर्णय लिया कि 25 वर्षों के लिए पंजाब नगरपालिका अधिनियम या पंजाब शहरी अचल संपत्ति अधिनियम में परिकल्पित कोई गृह-कर या संपत्ति कर आदि नहीं लगाया जाएगा। यह आश्वासन और नीति की घोषणा निम्नलिखित प्रभाव के लिए थी:

चंडीगढ़ में निजी मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के उद्देश्य से ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, मरला टैक्स और पंजाब अर्बन अचल संपत्ति अधिनियम, 1951 और पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1911 के प्रावधानों के संचालन से 25 साल के लिए छूट देने का फैसला किया है। इसी प्रकार कार्यकाल की सुरक्षा (शहरी अचल संपत्ति) विधेयक जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति एक मकान/एक दुकान की एक इकाई से अधिक आवासीय/व्यावसायिक परिसर यदि उन्हें अधिशेष घोषित करने का प्रस्ताव है, तो यह 25 वर्षों तक चंडीगढ़ पर भी लागू नहीं होगा।

इस आश्वासन को उत्तरदाताओं द्वारा उनके मूल रिटर्न के साथ-साथ अतिरिक्त हलफनामे दोनों में स्वीकार किया जाता है जिसमें आश्वासन के शब्दों को भी पुनः प्रस्तुत किया जाता है जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए शब्दों के समान है।

8. याचिका के पैरा 22 में कही गई बातों के अनुसार, चंडीगढ़ से सांसद श्री ए. एन. विद्यालंकार ने 9 जून, 1971 को संसद में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री के. सी. पंत से चंडीगढ़ के लिए एक निर्वाचित निकाय स्थापित करने की सलाह के बारे में पूछताछ की थी। माननीय मंत्री द्वारा इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था और इसका एक कारण यह बताया गया था कि तत्कालीन पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था कि चंडीगढ़ के विकास के हित में 25 वर्षों तक कोई नगरपालिका कर नहीं लगाया जाएगा और आगे यह भी कहा गया कि स्थानीय करों को लगाए बिना, किसी भी निर्वाचित निकाय के लिए अपने कार्यों को जारी रखना संभव नहीं होगा। उस समय संघ राज्य क्षेत्र का पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था।

9. यह घोषणा 10 जून, 1971 को अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित एक खबर के आधार पर की गई थी। इसमें इनकार नहीं किया गया था। उत्तर-पत्र ों द्वारा स्पष्ट शब्द। केवल यह उत्तर दिया गया था कि इससे संबंधित कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही एक नोटिस की प्रति अनुलग्नक पी एच है। \* आपत्तियां दर्ज होने के बाद, उसी पर निर्णय लिया गया। 24 अगस्त, 1977 को आकलन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों में से एक की प्रति, आपत्तियों को खारिज करते हुए और अंत में गृह कर की राशि का आकलन करते हुए अनुलग्नक पी. 13 है।

10. याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि 1959 में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा 25 साल की अवधि के लिए चंडीगढ़ शहर में भूमि और भवनों पर हाउस टैक्स सहित कोई भी कर नहीं लगाने के स्पष्ट आश्वासन के मद्देनजर, 1966 के पुनर्गठन के बाद एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को वचन पत्र के सिद्धांत के तहत रोक दिया गया था। इस अवधि की समाप्ति से पहले शुल्क लगाने से हाउस टैक्स। दूसरे शब्दों में, मई, 1984 से पहले कोई गृह कर नहीं लगाया जा सकता था। इस लेवी को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी कि! 1957 के संशोधन अधिनियम द्वारा, नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 और 62 में निहित

गृह कर लगाने से संबंधित प्रावधानों को तत्कालीन पंजाब विधानमंडल द्वारा चंडीगढ़ शहर में लागू नहीं किया गया था। जुलाई, 1968 में मुख्य आयुक्त द्वारा इन उपबंधों को प्रधान अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने और जुलाई, 1968 में मुख्य प्रशासक द्वारा चंडीगढ़ शहर में इन उपबंधों को लागू करने की एक अन्य अधिसूचना को शामिल करने वाली अधिसूचनाएं दूषित हो गई थीं क्योंकि वे आवश्यक विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त हैं। यह भी तर्क दिया गया था कि हाउस टैक्स नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 में उल्लिखित तरीके से और उद्देश्यों के लिए लगाया जा सकता है। चूंकि इस अधिनियम की धारा 4, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में नगरपालिका के गठन का प्रावधान था, को इस समय तक चंडीगढ़ शहर पर लागू नहीं किया गया था और नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 के तहत परिकल्पित अलग नगरपालिका निधि का गठन भी नहीं किया गया था, इसलिए गृह कर लगाना भी नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 और 61 के अंतर्गत आता है।

11. प्रतिवादियों की ओर से हलफनामे और डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से दिए गए जवाब के अनुसार, हालांकि तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा मई, 1959 में दिए गए आश्वासन, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, को स्वीकार कर लिया गया था, फिर भी यह स्पष्ट रूप से और जोरदार रूप से इनकार किया गया था कि हाउस टैक्स लगाने में चंडीगढ़ प्रशासन के रास्ते में वचन पत्र का सिद्धांत बाधा है। चूंकि इसे लगाने का निर्णय सरकार की नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप और स्वच्छता आदि जैसी नगरपालिका सेवाओं को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए किए जाने वाले निरंतर बढ़ते व्यय को ध्यान में रखते हुए लिया गया था चंडीगढ़ शहर विकसित हुआ है और जनसंख्या भी कई गुना बढ़ गई है। अतिरिक्त हलफनामे में 1 दिसंबर, 1972 से चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त के कार्यालय में हाउस टैक्स लगाने और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए करों के माध्यम से संसाधन जुटाने की वांछनीयता, कचरे के संग्रह और निपटान आदि के लिए अतिरिक्त वाहन प्रदान करने के बारे में सोच का एक विस्तृत (इतिहास और पृष्ठभूमि) दिया गया है। इसे रिटर्न के पैराग्राफ 23 में निम्नानुसार टाल दिया गया था: -

"लोकतांत्रिक सरकार का काम असंभव हो जाएगा यदि पिछली सरकारों द्वारा की गई घोषणाओं से विशेष नीतियों को बदलने की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है।

अन्य विवाद के संबंध में, यह कहा गया था कि राज्य सरकार और मुख्य आयुक्त को प्रधान अधिनियम की धारा 7-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियां अत्यधिक डेले-एल का मामला नहीं थीं।

अधिनियम की योजना द्वारा ही दिशा-निर्देश और दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे। इस बात पर जोर दिया गया कि हाउस टैक्स लगाना काफी वैध था और इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी।

स्त्री-विषयक

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा गृह कर लगाने की वैधता और सुदृढ़ता को चुनौती देने वाले हमले का मुख्य जोर दो गुना है, अर्थात्, हाउस टैक्स की लेवी वचन-पत्र के साथ-साथ आवश्यक विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर अस्थिर है। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सिब्बल के अनुसार, अन्याय से बचने और कानूनी धोखाधड़ी को रोकने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड के साथ-साथ इस देश में न्यायालयों द्वारा समानता के आधार पर समय के साथ वचन-पत्र या न्यायसंगत एस्टोपेल का सिद्धांत विकसित किया गया है। मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय के मैसर्स के मामले में उनके लॉर्डशिप के नवीनतम निर्णय पर भरोसा किया गया है। *मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*, 12 दिसंबर, 1978 को दिए गए। भगवती, जे., जिन्होंने इसमें न्यायालय की ओर से बात की, ने कहा,

"इसलिए, वचन पत्र का सही सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि जहां एक पक्ष ने अपने शब्दों या आचरण से दूसरे को एक स्पष्ट और स्पष्ट वादा किया है, जिसका उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी संबंधों को प्रभावित करना है, यह जानते हुए या इरादा रखते हुए कि यह दूसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा जिसके साथ कार्रवाई की जाएगी।

वादा किया गया है और वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है, वादा इसे बनाने वाले पक्ष के लिए बाध्यकारी होगा, और वह इससे पीछे हटने का हकदार नहीं होगा, अगर पार्टियों के बीच हुए व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा करने की अनुमति देना अनुचित होगा, और यह इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि पार्टियों के बीच पहले से कोई संबंध है या नहीं।

कानून के बयानों की बारीकी से जांच करने के बाद, जैसा कि अमेरिका में विभिन्न न्यायविदों और न्यायालयों द्वारा टिप्पणी की गई है! और इंग्लैंड और समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विश्लेषण करते हुए, इस निर्णय में वचन पत्र के क्षेत्र में कानून के निम्नलिखित प्रस्ताव निर्धारित किए गए थे:

- I. जहां सरकार यह जानते हुए या इरादा रखते हुए कोई वादा करती है कि उस पर वादा करने वाले द्वारा कार्रवाई की जाएगी और वास्तव में, उस पर भरोसा करने वाला अपनी स्थिति को बदल देता है, तो सरकार वादे से बाध्य होगी और वादा करने वाले के इशारे पर सरकार के खिलाफ वादा लागू किया जाएगा, भले ही वादे के लिए कोई विचार नहीं किया गया हो और वादा औपचारिक के रूप में दर्ज नहीं किया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत आवश्यक अनुबंध;
- II. सरकार वचन पत्र के नियम की प्रयोज्यता से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकती है और इस आधार पर उसके द्वारा किए गए वादे को अस्वीकार नहीं कर सकती है कि इस तरह के वादे से उसकी भविष्य की कार्यकारी कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। सिद्धांत अपनी सरकारी, सार्वजनिक या कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में सरकार के खिलाफ पूरी तरह से लागू होता है;
- III. सिद्धांत नगर निगम जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ समान रूप से लागू होता है;
- IV. कानून द्वारा लगाए गए दायित्व या दायित्व की किशोरावस्था में वचन पत्र का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है;
- V. विधायी शक्तियों के प्रयोग के विरुद्ध कोई वचन पत्र नहीं हो सकता;
- VI. जैसा कि वचन पत्र का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, समानता की आवश्यकता होने पर भी ऐसा ही होगा।
- VII. खुले के लिए खुला होगा! सरकार उन तथ्यों और परिस्थितियों को प्रकाश में लाए जो बाद में यह दर्शाने के लिए विकसित हो सकते हैं कि सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करना अन्यायपूर्ण होगा और ऐसी स्थिति में, अदालत वादा करने वाले के पक्ष में इक्विटी नहीं जुटाएगी, या यदि सरकार को वादे को पूरा करने की आवश्यकता होती है तो सार्वजनिक हित पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा। अदालत को सरकार द्वारा एक नागरिक से किए गए वादे को पूरा करने में सार्वजनिक हित को संतुलित करना होगा <sup>1</sup>, जिसने नागरिक को कार्य करने या अपनी स्थिति को बदलने के लिए प्रेरित किया है और यदि सरकार द्वारा वादे को पूरा करने की आवश्यकता होती है तो सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना है;
- VIII. वादे को पूरा करने के दायित्व को आवश्यकता या आवश्यकता के कुछ "अनिश्चित या अज्ञात" आधारों पर छूट नहीं दी जा सकती है;
- IX. केवल नीति में परिवर्तन का दावा सरकार को दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा; और यहां तक कि जहां ऐसा कोई अभिभावी सार्वजनिक हित नहीं है, तब भी वह इसके लिए सक्षम हो सकता है! सरकार को एक उचित नोटिस देने के वादे से पीछे हटना चाहिए, जिसे



औपचारिक नोटिस की आवश्यकता नहीं है, जिससे वादा करने वाले को अपना पद फिर से शुरू करने का उचित अवसर दिया जा सके; बशर्ते, निश्चित रूप से, यह (प्रोमिसर के लिए यथास्थिति को बहाल करने के लिए संभव है)।

कानून के उपर्युक्त प्रस्तावों को निर्धारित किया गया था: *भारत संघ और अन्य* में निर्णयों के अनुपात की पुष्टि करते हुए। *मैसर्स एंग्लो अफगान एजेंसियां और अन्य, बॉम्बे के कलेक्टर बनाम बॉम्बे शहर के नगर निगम और अन्य* और *सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कं, लिमिटेड, और एक अन्य*। *उल्हासनगर नगर परिषद और दूसरा*।

13. *आबकारी आयुक्त में, [यूपी बनाम राम कुमार]*, 'उस समय देशी शराब की बिक्री को बिक्री कर से छूट दी गई थी

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के तहत जारी एक अधिसूचना द्वारा खुदरा द्वारा ऐसी शराब बेचने के लिए लाइसेंस की नीलामी। उत्तरदाताओं ने नीलामी में भाग लिया और सबसे अधिक बोली लगाने वाले होने के नाते, उन्हें देशी भावना की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए। लाइसेंस शुरू होने के अगले दिन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की जिसमें पहले की अधिसूचना को दरकिनारा कर दिया गया और इस तरह देश की भावना पर बिक्री कर लगाया गया। उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णयों की जांच के परिणामस्वरूप, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है एन *रामानाथ* वी। *केरल राज्य*, *केरल राज्य और दूसरा राज्य ग्वालियर 1 रेयॉन* एफ एस आई एल एफ सी जे *मैनुफैक्चरिंग (डब्ल्यू वी जी) कंपनी लिमिटेड, और अन्य*, अमेरिकी न्यायशास्त्र और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय, यह आयोजित किया गया था, -

"यह निर्णयों की एक श्रेणी द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि ^ अपनी विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में सरकार के खिलाफ हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

लेवी और छूट को वापस लेने को तदनुसार वैध माना गया था। यह निर्णय *मैसर्स मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स* मामले (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय में भी विचारणीय विषय था और यह कहा गया था-

उन्होंने कहा, 'अगला फैसला जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वह उत्तर प्रदेश *इलाहाबाद के आबकारी आयुक्त बनाम राम कुमार* (4 सुप्रा) के मामले में है। यह भी एक निर्णय था जिस पर राज्य की ओर से मजबूत निर्भरता रखी गई थी। यह सच है कि इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अब निर्णयों की एक श्रेणी द्वारा यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सरकार को उसकी विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उसके विरुद्ध हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन जिन कारणों से हम वर्तमान में कहेंगे, हमें नहीं लगता कि यह अवलोकन हमें भारत-अफगान एजेंसियों के मामले में प्रतिपादित कानून के बारे में एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय के कुछ पूर्व निर्णयों पर चर्चा करने के बाद पुन यह टिप्पणी की गई कि -

"इस प्रकार यह निर्णय में भरोसा किए गए निर्णयों से देखा जाएगा कि न्यायालय संभवतः इरादा नहीं कर सकता था।

एक पूर्ण प्रस्ताव निर्धारित करना कि अपनी सरकारी, सार्वजनिक या कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार के खिलाफ कोई वचन पत्र नहीं हो सकता है। यह भारत-अफगान एजेंसियों के मामले, सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मामले और टर्नर मॉरिसन के मामले में इस अदालत के फैसलों के बिल्कुल विपरीत होता और हमें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि

अदालत कभी भी इन पहले के फैसलों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किए बिना और उन पर अधिक निर्णय दिए बिना इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित करने का इरादा कर सकती थी। (इसलिए, हमारी राय है कि न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी)

आईएमराम कुमार का मामला भारत-अफगान एजेंसियों के मामले, सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मामले और टर्नर मॉरिसन के मामले (सरकार के खिलाफ वचन पत्र के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में) में लिए गए फैसलों के आधार पर हमारे द्वारा लिए जा रहे दृष्टिकोण के खिलाफ नहीं है।

14. इस प्रकार, राम कुमार के मामले (4 सुप्रा) में निर्धारित कानून के अनुसार, सरकार के संप्रभु, विधायी या कार्यकारी कार्यों के प्रयोग में उसके खिलाफ कोई वचन पत्र या न्यायसंगत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जबकि मेसर्स मोतीलाल पदमपत चीनी मिल के मामले में निर्णय के अनुपात के अनुसार। (सुप्रा), सरकार अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग करते समय इस सिद्धांत से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकती है और अपने वादों और आश्वासनों से तब तक बाध्य है जब तक कि (तथ्यों को साबित नहीं किया जा सकता है जो यह दर्शाता है कि इसके पक्ष में सार्वजनिक हित और इच्छिटी पर विचार करना उचित वादों से उत्पन्न होने वाले उपदेशों से बाधित नहीं होगा)। सुप्रीम कोर्ट के दो नवीनतम निर्णयों के बीच वचन पत्र के इस सिद्धांत के दायरे और दायरे के बारे में स्पष्ट रूप से मतभेद दिखाई देते हैं। इस नाजुक स्थिति का सामना करते हुए, इस न्यायालय को अपने लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाया गया है। यह प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है: संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत परिकल्पित कानून की घोषणा के रूप में उच्च न्यायालय पर (किस निर्णय का निर्णय बाध्यकारी है)?

15. मैटुलाल वी में / राधे लाई, (जब उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों के बीच विरोधाभास पाया गया, तो यह माना गया, -

"लेकिन कारण जो भी हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों में टिप्पणियों को समेटना संभव नहीं है।

निर्णय। ऐसा होने पर, हमें श्रीमती कमला सोनी के मामले में निर्णय के बजाय सरवटे टीबी के मामले में निर्णय का पालन करना पसंद करना चाहिए; मामला, जैसा कि पूर्व का निर्णय है \* 'बाद की तुलना में बड़ी बेंच।

निर्णय। ऐसा होने पर, हमें श्रीमती कमला सोनी के मामले में निर्णय के बजाय सरवटे टीबी के मामले में निर्णय का पालन करना पसंद करना चाहिए; मामला, जैसा कि पूर्व का निर्णय है \* ' ' बाद की तुलना में बड़ी बेच।

16. इन ई-स्टेट में, जॉफ बनाम यू.पी.राम चंद्र? त्रिवेदी में ऐसी ही स्थिति में, उनके लॉर्डशिप ने कहा,

पीठ ने कहा, 'यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में भी जहां उच्च न्यायालय को इस न्यायालय की बड़ी और छोटी पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बीच कोई विरोधाभास नजर आता है, वह बड़ी पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इस तरह के मामले में उच्च न्यायालय के लिए उचित रास्ता क्या है, जैसा कि भारत संघ बनाम केरल संघ मामले में इस न्यायालय ने देखा है । सुहरामनियन जिसमें हम में से एक पक्ष था, (यह पता लगाने और उनके द्वारा व्यक्त की गई राय का पालन करने की कोशिश करना है)

"इस न्यायालय की बड़ी पीठें न्यायालय की छोटी पीठों द्वारा व्यक्त की गई पीठों को वरीयता देती हैं, जो प्रैक्टिस करती हैं: कानून के शासन के रूप में इसे कठोर बनाया गया है, इसके बाद ऐसा किया जाता है " खुद अदालत है।

वर्तमान मामले में, राम कुमार के मामले (सुप्रा) में निर्णय, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरकार के संप्रभु विधायी और कार्यकारी कार्यों का पालन करते हुए उसके खिलाफ कोई वचन पत्र नहीं हो सकता है, चार-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा है, जबकि मैसर्स के मामले में है। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स का मामला (सुप्रा), दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा चलाया जाता है, हालांकि यह बाद में होता है। "उपरोक्त दो निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की उक्ति को ध्यान में रखते हुए, मैं राम कुमार के मामले में निर्धारित कानून से बाध्य हूं ।

17. प्रतिवादी नोटिस के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, उनकी इस दलील पर विचार किया जा सकता है कि वह मैसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स के मामले (सुप्रा; ) में निर्णय की शुद्धता को चुनौती देते हैं, जहां तक यह माना गया था कि अपने कार्यकारी कार्यों का पालन करते समय सरकार के लिए भी वचन पत्र का सिद्धांत बाध्यकारी था। हालांकि, इस पर विचार करना इस न्यायालय का काम नहीं है; यह प्रश्न। यह 89 में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के लिए होगा देश, यानी सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक राय में स्पष्ट विरोधाभासों को देखते हुए अंततः और स्पष्ट रूप से कानून बनाकर विवाद को हल करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वचन पत्र या समतामूलक सिद्धांत का उचित दायरा और आयाम उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण महत्व का विषय है, जिनके पास सरकार के साथ-साथ सरकार के गंभीर आश्वासनों और वादों पर कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो सार और सार रूप में एक पार्टी सरकार है। सरकारों से अपेक्षा की जाती है, यहां तक कि प्रामाणिक भी कि वे समय-समय पर अपनी नीतियों को बदलें और इस प्रकार पहले से किए गए वादों को दरकिनार करें।

17. चंडीगढ़ प्रशासन के वकील श्री ए स्वरूप द्वारा एक और तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले में, मुख्य आयुक्त द्वारा केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुलाई, 1968 में जारी अधिसूचना के अनुसरण में हाउस टैक्स लगाया गया था, जिसके तहत (नगरपालिका अधिनियम और अन्य संबद्ध प्रावधानों) की धारा 61 को मूल अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में शामिल किया गया था। और उसके बाद, अगस्त, 1968 में मुख्य प्रशासक द्वारा एक और अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत इन प्रावधानों को चंडीगढ़ शहर में लागू किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि ये दोनों अधिसूचनाएं प्रधान अधिनियम की धारा 7 ए के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में जारी की गई थीं। इसे ध्यान में रखते हुए, वास्तव में, सरकार ने विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में आवश्यक विधायी कार्य किए, न कि कार्यकारी कार्यों के रूप में। यहां तक कि मैसर्स के निर्णय के अनुपात के अनुसार भी। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स केस (सुप्रा), वचन पत्र का सिद्धांत विधायिका के खिलाफ लागू नहीं हो सका। इस प्रकार, हाउस टैक्स की लेवी इस हमले से बची हुई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सिब्बल ने इस तर्क का जोरदार खंडन किया। उनके अनुसार, विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए भी सरकार को स्वयं विधायिका के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और दूसरी बात, विधायिका द्वारा (प्रधान अधिनियम की धारा 7 ए के तहत सरकार को प्रदत्त शक्ति का उल्लंघन किया गया था (जैसा कि यह शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन का परिणाम था)। इस स्तर पर, (मैं श्री सिब्बल द्वारा उठाए गए

विवाद के केवल एक पहलू से चिंतित हूं। वचन पत्र के सिद्धांत के दायरे को निर्धारित करने के उद्देश्य से मैं जो कानून बनाता हूं, उसके विरुद्ध कार्यपालिका को विधायी शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के संबंध में आपत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक स्वतंत्र प्रश्न है जो वर्तमान विवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, हमें इस धारणा पर आगे बढ़ना होगा कि सरकार या मुख्य आयुक्त ने विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में और अनुमेय प्रत्यायोजन के दायरे में दूसरी अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 सहित अधिसूचना जारी करने में केंद्र सरकार की ओर से कार्य किया। इस स्तर पर प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने पर इस शक्ति का स्वरूप क्या है? चाहे वह विधायी हो या (कार्यपालिका) हो? कुछ इसी तरह के सवाल *नरिंदर चंद, हेम राज और अन्य भी उठे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपराज्यपाल, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य*। उस मामले में, नीलामी के समय, आबकारी और कराधान कलेक्टर ने घोषणा की कि भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर की बिक्री पर कोई बिक्री कर का भुगतान नहीं किया जाएगा। उस आश्वासन के बावजूद, सरकार ने अपीलकर्ताओं से बिक्री कर लगाया और एकत्र किया और इसे प्राप्त करने के लिए आगे कदम उठा रही थी। सरकार के अनुसार, जवाब में, उपायुक्त ने बोलीदाताओं को केवल यह बताया था कि सरकार भारत निर्मित विदेशी शराब पर बिक्री कर को हटाने के सवाल पर विचार कर रही थी और हिमाचल प्रदेश सरकार भारत निर्मित विदेशी शराब पर बिक्री कर को हटाने का निर्णय ले सकती है, लेकिन इसे लागू नहीं कर सकती है: निर्णय क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी। विधायिका के प्रतिनिधि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति के संबंध में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"कर लगाने की शक्ति निस्संदेह एक विधायी शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग विधायिका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है या, कतिपय शर्तों के अधधीन, विधानमंडल उस शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, परन्तु उस शक्ति का प्रयोग, चाहे विधायिका द्वारा हो या उसके प्रतिनिधि द्वारा, विधायी शक्ति का प्रयोग है। तथ्य यह है कि शक्ति कार्यपालिका को सौंपी गई है, उस शक्ति को कार्यकारी या प्रशासनिक शक्ति में परिवर्तित नहीं करता है। कोई भी न्यायालय किसी विधायिका को किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने का अधिदेश जारी नहीं कर सकता है। इसी तरह, कोई भी न्यायालय किसी अधीनस्थ विधायी निकाय को कानून बनाने या न करने का निर्देश नहीं दे सकता है, जिसे वह अधिनियमित करने में सक्षम हो सकता है।

उपर्युक्त मामले में निर्णय के अनुपात *को ध्यान में रखते हुए*, यह माना जाना चाहिए कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ ने गृह कर लगाने का निर्णय लेते समय और प्रधान अधिनियम की दूसरी अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 और अन्य प्रावधानों को शामिल करते हुए विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में विधायी कार्यों का प्रयोग किया। मई, 1959 में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन, कि आने वाले 25 वर्षों तक चंडीगढ़ में कोई कर नहीं लगाया जाएगा, किसी अन्य प्रकार के वचन पत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि विधायिका एक संप्रभु निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत कानून के संबंध में संप्रभु शक्तियों के साथ निवेश किया गया है। विधायी कार्यों का अभ्यास करते समय इसके प्रतिनिधि भी उस चरित्र में भाग लेते हैं। यदि किसी भी एस्टोपेल को बाध्यकारी माना जाता है, तो यह विधायिका को गृह कर के संबंध में एक निश्चित कानून पारित नहीं करने के अधिदेश की प्रकृति में होगा, जो किया नहीं जा सकता है। यह निर्विवाद है कि विधायिका के कानून के खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रत्यायोजित प्राधिकारी, जो वर्तमान मामले में मुख्य आयुक्त था (अयोग्य आक्षेपित अधिसूचना जारी करने में विधायिका की शक्ति का प्रयोग करते हुए) को वचन पत्र के सिद्धांत के आधार पर हमले से मुक्त रखा गया था।

18. दोनों पक्षों की ओर से कुछ तर्क भी दिए गए कि तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा 1984 तक कोई कर न लगाने के आश्वासन के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इक्विटी के हमले को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के पक्ष में न्यायसंगत विचारों के संबंध में सरकार द्वारा जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाए। 1959 में कथित आश्वासन के बाद प्रशासन के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप के अनुसार, चंडीगढ़ एक पूर्ण शहर के रूप में विकसित हो गया था और इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या भी कई गुना बढ़ गई थी, प्रशासन को जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, फायर ब्रिगेड आदि जैसी पर्याप्त नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने का कठिन सामाजिक कर्तव्य निभाना पड़ता है और हाउस टैक्स के स्रोत का दोहन किए बिना इन कार्यों का

निर्वहन करना संभव नहीं था। सभी नगरपालिका समितियों द्वारा इसका सहारा लिया गया था और यह कि मुख्य प्रशासक को संशोधन अधिनियम के तहत एक नगरपालिका समिति की सभी शक्तियां प्रदान की गई थीं। प्रशासन की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे का जोरदार संदर्भ दिया गया था, जिसमें हाउस टैक्स लगाने की विस्तृत पृष्ठभूमि दी गई थी। श्री सिब्बल के अनुसार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील

400

देस राज जुनेजा और अन्य, वी/भारत संघ और अन्य  
(हरबन लाई, जे।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाउस टैक्स लगाना कार्यपालिका द्वारा नीति में बदलाव का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स के मामले (सुप्रा) में स्पष्ट अनुपात के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों की पुष्टि करते हुए कार्यकारी को अपने उपक्रमों और प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का अधिकार नहीं देता है। तथापि, इस स्पष्ट निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए मामले के इस पहलू की जांच और विचार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है कि वचन पत्र का सिद्धांत वर्तमान मामले की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है।

19. याचिकाकर्ताओं की ओर से दूसरा हमला जो अधिक असुरक्षित और वजनदार है, वह यह है कि प्रिंसिपल एक्ट की दूसरी अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 और धारा 84 तक अन्य संबद्ध प्रावधानों सहित लागू की गई अधिसूचना और चंडीगढ़ में इन प्रावधानों को लागू करने वाली दूसरी अधिसूचना दूषित और अस्थिर है क्योंकि इसे विधायिका के प्रतिनिधि द्वारा एक ऐसे क्षेत्र में जारी किया गया था जो सिद्धांत से प्रभावित है। विधायी शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन। कानून का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार से शुरू होने वाले निर्णयों की श्रृंखला में विचार और चर्चा का विषय रहा है। अनुच्छेद 143 भारत का संविधान और दिल्ली विधि अधिनियम। इस मामले में, प्रांतीय सरकार को एक अधिसूचना द्वारा दिल्ली प्रांत में ब्रिटिश भारत के किसी भी अधिनियम को लागू करने के लिए एक कानून द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी। कई फैसले अलग-अलग दिए गए थे। पतंजलि शास्त्री जे, जो इस मामले का फैसला करने वाली पीठ के माननीय न्यायाधीशों में से एक थे, ने बाद में काठी रानिंग रावत बनाम काठी रानिंग रावत मामले में टिप्पणी की। सौराष्ट्र राज्य, इस मामले के बारे में निम्नानुसार है:

"दूसरे बिंदु पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दावा किया कि बहुमत का विचार सही है। भारत के संविधान और दिल्ली कानून अधिनियम, 1912, आदि, ने उनके तर्क का समर्थन किया। उन्होंने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया (उस मामले में दिए गए कई निर्णयों में पाए गए कुछ आदेशों के साथ)। हालांकि निस्संदेह कुछ निर्दिष्ट अधिनियमों की संवैधानिकता के संबंध में निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे गए थे, प्रत्येक मामले में तर्क अलग थे, और यह कहना मुश्किल है कि बहुमत द्वारा कोई विशेष सिद्धांत निर्धारित किया गया है जो अन्य मामलों के निर्धारण में सहायता कर सकता है।

बॉम्बे राज्य में बनाम नरोत्तमदास जेठाभाई और एक अन्य, बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट, अधिनियम को वैध माना गया था जिसके द्वारा सिटी कोर्ट बनाया गया था, लेकिन जे पावर प्रांतीय सरकार में निहित थी, जो इस सिटी सीबीर्ट को 25,000 रुपये से अधिक मूल्य का अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकती थी। ' यह . आयोजित किया गया था, -

' ( "प्रावधान केवल नीति के प्रवर्तन से संबंधित है, जो, विधायिका ने स्वयं निर्धारित किया है। वही; कानून भरा हुआ था।

; और जब विधायी कक्ष अनुमति देता है, तो प्रांतीय सरकार को सिटी कोर्ट के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को एक निश्चित राशि तक बढ़ाने की अनुमति मिलती है, जिसे कानून द्वारा ही निर्दिष्ट किया गया था। प्रांतीय सरकार को जो करना है वह कोई काम नहीं करना है। चरित्र-दोष; उसे विधायिका की इच्छा को निष्पादित करना होता है और यह निर्धारित करना होता है कि किस समय और किस सीमा तक, उसके भीतर है। , विधायिका द्वारा निर्धारित सीमाएं, न्यायालय का विस्तार किया जाना चाहिए। यह, एक है . सशर्त कानून की प्रजातियां जो सीधे रानी वी में उल्लिखित सिद्धांत के भीतर आते हैं। बर्ग, 5 आईए 178 (पीसी)।

20. राजनारायण सिंह बनाम अध्यक्ष, पटना प्रशासन समिति, पटना और एक अन्य, दिल्ली विधि अधिनियम में आसानी (सुप्रा) का अनुपात समझाया गया था और यह कहा गया था, -

एक कार्यकारी प्राधिकरण को मौजूदा या भविष्य के कानूनों को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आवश्यक विशेषता में नहीं। वास्तव में जो एक आवश्यक विशेषता का गठन करता है, उसे सामान्य रूप से [शब्दों] में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसमें नीति में बदलाव शामिल नहीं हो सकता ..... है।

इसमें, बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 104 को पटना ग्राम क्षेत्र तक विस्तारित करने वाली अधिसूचना अधिनियम की नीति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई थी और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया गया था।

21. प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप के अनुसार, विधायी नीति स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी।

संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसके द्वारा धारा 7-क को प्रधान अधिनियम में जोड़ा गया था (इसमें, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य चंडीगढ़ शहर को नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना था (जिन्हें नगरपालिका अधिनियम में शामिल किया गया है)। के. रंगनाथन और एक अन्य वी. मद्रास सरकार और अन्य को इस संबंध में सेवा में लगाया गया था, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि उद्देश्यों और कारणों के कथन को केवल उस समय की विद्यमान स्थितियों का पता लगाने के बहुत सीमित उद्देश्य के लिए संदर्भित किया जा सकता है जिसने विधेयक के प्रायोजकों को इसे पेश करने के लिए प्रेरित किया और उस बुराई की सीमा और तात्कालिकता जिसे उन्होंने दूर करने की मांग की थी। यह भी स्पष्ट रूप से निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

J

"उद्देश्यों और कारणों का कथन निश्चित रूप से सहायता के रूप में स्वीकार्य नहीं है; एक कानून का निर्माण।

में हरिशंकर बागला और एक अन्य बहुत। मध्य प्रदेश राज्य, विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन की सीमा और दायरे को महाजन, सीजे द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था, जिन्होंने न्यायालय की ओर से निम्नानुसार बात की थी: मैं

पीठ ने कहा, "विधायिका किसी उपाय के संबंध में विधायी नीति निर्धारित करने का कार्य और इसे (आचरण के नियम के रूप में तैयार करने का) नहीं सौंप सकती। (विधायिका को कानून की नीति और कानूनी सिद्धांतों की घोषणा करनी चाहिए जो [किसी भी दिए गए मामलों को नियंत्रित करने के लिए हैं और (कानून को निष्पादित करने के लिए अधिकारियों, या सत्ता में निकाय का मार्गदर्शन करने के लिए एक मानक प्रदान करना चाहिए)। आवश्यक विधायी कार्य में (विधायी नीति के निर्धारण या पसंद में और (औपचारिक रूप से उस नीति को बाध्यकारी नियम में लागू करना) शामिल है।

22. इंदर सिंह बनाम भारत राजस्थान राज्य, प्रत्यायोजित कानून और सशर्त कानून के बीच के अंतर को इस प्रकार समझाया गया था:

पीठ ने कहा, "जब कोई उपयुक्त (विधायिका कानून बनाती है और किसी बाहरी प्राधिकारी को ऐसे क्षेत्र में इसे लागू करने के लिए अधिकृत करती है)

ऐसे समय में, जैसा कि वह निर्णय ले सकता है, यह सशर्त है और प्रत्यायोजित कानून नहीं है और ऐसा कानून वैध है।

मैं

23. इन्फ भटनागर स सेंट कंपनी लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य, हरिशंकर बागडब्यू मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात की फिर से पुष्टि की गई।!

24. पंडित बनारसी दास भनोट बनाम मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रांत और बरार बिक्री कर अधिनियम (1947 का XXI) के कतिपय उपबंधों को चुनौती दी गई थी जिसके तहत राज्य सरकार को उन वस्तुओं से संबंधित अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी जिन पर (बिक्री कर लगाया जा सकता था और बिक्री कर की दरें भी निर्धारित की जा सकती थीं। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

"यह असंवैधानिक नहीं है कि विधायिका कराधान कानूनों के कामकाज से संबंधित विवरण को निर्धारित करने के लिए कार्यपालिका पर छोड़ दे, जैसे कि उन व्यक्तियों का चयन जिन पर कर; वस्तुओं के विभिन्न वर्गों के संबंध में जिन दरों पर यह प्रभारित किया जाना है, और इसी प्रकार की दरें निर्धारित की जानी हैं। छूट से संबंधित अनुसूची में संशोधन करने के लिए धारा 6 (2) द्वारा राज्य सरकार को दी गई शक्ति इस विषय से संबंधित स्वीकृत विधायी प्रथा के अनुरूप है, और असंवैधानिक नहीं है।

तथापि, दिल्ली नगर निगम बनाम दिल्ली नगर निगम में। बिड़ला कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली और अन्य, उपर्युक्त निर्णय का अनुपात इस आशय का है कि कर की दरों का निर्धारण कानून की अनिवार्य विशेषता नहीं थी, इस पर सहमति नहीं हुई थी और इसे आयोजित किया गया था-

" बनारसी दास के मामले में यह टिप्पणी कि कर की दरें कानून की आवश्यक विशेषताएं नहीं हैं, इसलिए इस संबंध में, बहुत व्यापक रूप से कहा गया प्रतीत होता है, हालांकि यह हो सकता है।





,उन्होंने स्वीकार किया कि कराधान की दरें भी कुछ क्षेत्रों में हो सकती हैं उचित मार्गदर्शन के साथ एक अधीनस्थ प्राधिकरण को रुख सौंपा जाना चाहिए और इस संबंध में सुरक्षा उपायों और सीमाओं के अधीन होना चाहिए।<sup>1</sup>

'25. में *निगम: कलकत्ता और एक अन्य वी। स्वतंत्रता* सिनेमा, (21-ए), नगरपालिका समिति ने सिनेमा घरों पर लाइसेंस शुल्क 400 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया था।<sup>4</sup> 1958 में कैदुत्ता नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रति वर्ष। यह माना गया था कि दरों का निर्धारण विधायी शक्ति, कराधान का सार नहीं था। हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसी शक्ति प्रदान करते समय, विधायिका को इस तरह के निर्धारण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। यह भी माना गया था कि यह एक अच्छा मार्गदर्शन होगा यदि यह कानून के उद्देश्य की उपलब्धि की ओर जाता है जिसने शक्ति को प्रत्यायोजित किया है।  
मैं

आर 26. *दिल्ली की नगर निगम* बहुत। *बिड़ला कपास, कताई और बुनाई मिल्स, दिल्ली और अन्य*, सुप्रा, उनके लॉर्डशिप ने पिछले निर्णयों की बारीकी से जांच करने के बाद कहा कि आवश्यक विधायी कार्य जो विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के नियम के रूप में इसका निर्माण है, उसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। विधायिका के रूप में संभवतः एक जटिल विकासशील समाज के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप सभी विवरणों पर काम नहीं कर सकता है। अधिक महत्वपूर्ण 'विधायी कार्यों' में भी व्यस्त है, कार्यपालिका को विवरण सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि प्रतिनिधिमंडल का सिद्धांत भी अंतर्निहित खतरों से ग्रस्त है, विधायिका को 'प्राधिकारी को सौंपते समय स्वयं को स्वीकार करना चाहिए और प्रतिनिधि के लिए दिशा-निर्देशों को अस्वीकार करना चाहिए'। उनके ऑर्डशिप में दिशानिर्देशों की प्रकृति और दायरे का विस्तृत अध्ययन भी शामिल है। यह माना गया था कि मार्गदर्शन करों की अधिकतम दरों को प्रदान करने के रूप में हो सकता है जिसके लिए एक स्थानीय निकाय को विवेकाधिकार दिया जा सकता है। अगर यह प्रतिनिधिमंडल एक निर्वाचित निकाय के लिए है, यह तथ्य कि निर्वाचित सदस्यों को समय-समय पर चुनाव के लिए मतदाताओं के पास जाना होता है, अनुचित रूप से कार्य न करने के लिए एक बड़ी जांच के रूप में कार्य करता है। यह भी माना गया था कि आवश्यकता, निगम और जिन वस्तुओं की उपलब्धि के लिए इसे कार्य करना है, उन्होंने भी एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य किया। यह प्रावधान कि प्रत्यायोजित प्राधिकारी की किसी भी अधिसूचना या निर्णय को एक निश्चित न्यूनतम अवधि के लिए विधायिका के समक्ष रखा जाना आवश्यक था, ने भी मार्गदर्शन प्रस्तुत करने में एक लंबा रास्ता तय किया।



2.7": "याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सिब्बल के अनुसार, बी। शर्मा राव वी। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने आवश्यक विधायी कार्यों के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण अनुपात निर्धारित किया है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। उसमें, अगस्त, 1962 में, पांडिचेरी को एक अलग केंद्रीय प्रशासित इकाई के रूप में गठित किया गया था और इस क्षेत्र में एक विधान सभा भी स्थापित की गई थी। उक्त विधायिका ने पांडिचेरी को पारित किया। सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1965 धारा 2 के तहत, मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 को एक अधिसूचना द्वारा लागू करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान की गई थी। इस शक्ति के अनुसरण में पांडिचेरी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। न केवल तत्कालीन मद्रास जनरल) सलीवैटैक्स अधिनियम, 1959; लेकिन बाद के संशोधनों को पांडिचेरी में भी लागू किया गया था। उनके 'सर्वोच्च प्रभुत्व' के अनुसार। पांडिचेरी विधायिका ने अपने आवश्यक विधायी कार्यों को त्याग दिया था और यह आयोजित किया गया था,

; "तो सवाल यह है कि क्या मद्रास अधिनियम का विस्तार करने में; तरीके से और करने के लिए; धारा 2 (1) के तहत यह क्या था? पांडिचेरी विधायिका ने प्रधान अधिनियम के तहत पद त्याग दिया

- मद्रास विधायिका के पक्ष में इसकी विधायी शक्ति।

यह स्पष्ट है कि विधानसभा ने अपने (अधिनियम के तहत सौंपे गए विधायी कार्यों को करने से इनकार कर दिया) यह हो सकता है कि केवल इनकार करने का मतलब त्याग नहीं हो सकता है, अगर विधायिका कानून की पूरी औपचारिकता से गुजरने के बजाय किसी अन्य विधायिका द्वारा दूसरे अधिकार क्षेत्र के लिए अधिनियमित मौजूदा कानून पर अपना दिमाग लगाती है। इस तरह के अधिनियम को अपनाता है और इसे विस्तारित करने के लिए अधिनियमित करता है

- अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र के लिए। ऐसा करते हुए, शायद यह कहा जा सकता है कि इसने विस्तार करने के लिए एक नीति निर्धारित की है

एक अधिनियम को लागू करना और कार्यपालिका को लागू करने का निर्देश देना और; ऐसे अधिनियम को लागू करें। लेकिन जब यह न केवल अपनाया जाता है! ऐसा अधिनियम लेकिन यह भी प्रावधान करता है कि इसके राज्यक्षेत्र पर लागू होने वाला अधिनियम अन्य विधायिका द्वारा भविष्य में संशोधित अधिनियम होगा, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संशोधित अधिनियम क्या होगा। इस तरह का मामला स्पष्ट रूप से होगा, 1 \* एक मन का प्रयोग न करना और एक मना करना

.; इसका गठन करने वाले उपकरण द्वारा इसे सौंपे गए कार्य का निर्वहन करें। यह देखना मुश्किल है कि इस तरह के प्रभाव कैसे नहीं होते हैं।

कम से कम उस विशेष मामले के संबंध में किसी अन्य विधायिका के पक्ष में त्याग या अपमान।

इस प्रकार अधिसूचनाओं को खराब माना गया और रद्द कर दिया गया।

8. प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने अपने प्रस्ताव को प्रचारित करने के लिए कि आक्षेपित अधिसूचनाएं अनुमेय विधायी शक्ति की सीमा से अधिक नहीं हैं, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया, जो हालांकि, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई समर्थन नहीं देते हैं।

9. एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड में बहुत। अजमेर राज्य और अन्य, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को अनुसूची में विनिदष्ट किसी भी रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई थीं (अधिनियम के प्रारंभ के समय या बाद में धारा 27 के उपबंधों के अनुसार इसमें जोड़ी गई)। मार्च, 1950 में, अजमेर के आयुक्त ने अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें वस्त्र मिलों में रोजगार को शामिल करने के अपने इरादे के बारे में तीन महीने का नोटिस दिया गया था (अनुसूची में एक अतिरिक्त मद के रूप में)। अक्टूबर, 1950 में अंतिम अधिसूचना जारी की गई। दायर रिट याचिका में चुनौतियों में से एक शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर इन अधिसूचनाओं की वैधता के लिए थी। इस विवाद को खारिज कर दिया गया और इसे आयोजित किया गया,

"विधायी नीति इस पर स्पष्ट है . [न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948] का चेहरा। इसका उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी का सांविधिक निर्धारण करना है ताकि श्रम के शोषण की संभावना को समाप्त किया जा सके। विधायिका निस्संदेह इस अधिनियम को सभी उद्योगों पर लागू नहीं करना चाहती थी, बल्कि (केवल उन उद्योगों पर जहां असंगठित श्रम या मजदूरी के प्रभावी विनियमन के लिए उचित व्यवस्था की कमी के कारण या यदि किसी विशेष उद्योग में मजदूरों की मजदूरी बहुत कम थी) लागू करने का इरादा था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में ट्रेडों की सूची तैयार की गई है, लेकिन (सूची संपूर्ण नहीं है (एक और यह विधायिका की नीति है कि इसे प्रस्तुत न किया जाए)।

एक बार में और हर समय, किन उद्योगों (अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए) पर लागू किया जाना चाहिए।

में

यह भी माना गया कि धारा 27 को लागू करके, विधायिका ने किसी भी तरह से अपनी आवश्यक शक्तियों को नहीं छीना है, या प्रशासनिक प्राधिकरण को एक सहायक या अधीनस्थ शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं सौंपा है, जिसे पूरा करने के लिए आवश्यक समझा गया था। अधिनियम का उद्देश्य और नीति।

30. प्रतिवादियों के वकील आनंद स्वरूप के अनुसार, मुख्य आयुक्त और मुख्य प्रशासक को प्रधान अधिनियम की धारा 7-ए द्वारा प्रदान की गई शक्ति प्रदान की गई शक्ति प्रदान की गई शक्ति के समान थी; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत। श्री सिब्बल के अनुसार, (यह शक्ति प्रदान करना मूल रूप से और/काफी भिन्न है और समान नहीं है।

31. में *भारत संघ और अन्य बनाम भानामल गुलजारीमल लिमिटेड और अन्य*, आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 3 और 4 के तहत समय-समय पर लोहे और इस्पात की न्यूनतम कीमतें तय करने के लिए केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान की गई थीं। इस शक्ति के अनुसरण में, एक आदेश प्रख्यापित किया गया था जिसके अनुसार एक वैधानिक निषेध लगाया गया था। निर्दिष्ट व्यक्ति किसी भी लोहे या इस्पात को बेचने या बेचने की पेशकश करते हैं (इसमें निर्धारित अधिकतम कीमतों से अधिक मूल्य)। धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया था। यह सोचा गया कि लोहे [और इस्पात] के स्टॉक को उचित कीमतों पर समान वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाए। यह आयोजित किया गया था, -!

"यह स्पष्ट है कि लौह और इस्पात खंड की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करके आईआईबी सीधे धारा 3 में निर्धारित विधायी उद्देश्य को पूरा करता है क्योंकि अधिकतम कीमतों के निर्धारण से उचित कीमतों पर समान वितरण के लिए लोहे और इस्पात का स्टॉक उपलब्ध होगा।

इस प्रकार प्रावधान को संवैधानिक माना गया और अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल के आधार पर प्रभावित नहीं किया गया।

32. *मोहेमेदली और अन्य* में वी। *भारत संघ और अन्य*, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, किस पर लागू था?

प्रत्येक प्रतिष्ठान जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में कार्यरत कारखाना था और जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत थे। यह उन प्रतिष्ठानों पर भी लागू होना था जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। केंद्र सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 1 के तहत इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1961 में एक अधिसूचना जारी की जिसमें प्रतिष्ठानों की कक्षाओं में होटल और रेस्तरां को भी शामिल किया गया था। इस अधिसूचना को विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर दूषित के रूप में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तर्क को खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि यदि किसी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कानून के अंतर्निहित सिद्धांत को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था और उचित मानकों और मानदंड भी निर्धारित किए गए थे, लेकिन विशेष मामलों के संबंध में केवल उन सिद्धांतों और मानकों के आवेदन को कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया था, शक्ति का ऐसा प्रत्यायोजन अनुमत सीमाओं के भीतर था जिसे यह भी माना गया था:-

"दूसरी ओर, यदि उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों और प्रस्तावना सहित कानून के प्रावधानों की समीक्षा से न्यायालय सिद्धांतों और मानकों के बारे में अनुमान लगाता है, तो प्रतिनिधि को केवल व्यक्तिगत मामलों में कानून लागू करने का कार्य नहीं सौंपा गया है, बल्कि विधायी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सौंपा गया है।

33. *बिमला चंद्र बनर्जी* बनाम *मध्य प्रदेश सरकार* ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 के खंड (डी) और (एच) के तहत अपनी शक्तियों का कथित प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा शराब लाइसेंसधारकों को शराब की ऐसी मात्रा पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाने की मांग की गई थी, जिसे उन्हें उठाना था, लेकिन उन्होंने वास्तव में उठाया नहीं था। यह माना गया

कि उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान ने नियम बनाने वाले प्राधिकरण को शराब ठेकेदारों को दिए गए लाइसेंस के तहत आयात, निर्यात, परिवहन, निर्मित, खेती या एकत्र नहीं की गई किसी भी निर्यात योग्य वस्तुओं पर शुल्क लगाने का अधिकार नहीं दिया है। कराधान के मामलों में विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन की गुंजाइश निर्धारित करते हुए, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

"किसी भी उप-कानून या नियम या विनियमन द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि कानून जिसके तहत अधीनस्थ कानून नहीं विशेषरूप से इसे लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है, भले ही यह मान लिया जाए कि कर लगाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंपी जा सकती है।

r

34. सीआईएनआईसी ग्वालियर/रेयोनलमिल्सजीएमएफजी में। (डब्ल्यूवीजी), कं, लिमिटेड, एवी। बिक्री कर के सहायक आयुक्त और अन्य, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 (2) (डी) के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इस प्रावधान के द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर की दर निर्धारित नहीं की गई थी, परन्तु उपयुक्त राज्य के अंदर वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लागू दर को 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में अपनाया जाता था। उनके लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया था कि ऐसा करते हुए, संसद ने विधायी नीति को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया था क्योंकि यह प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय बिक्री कर किसी भी मामले में स्थानीय बिक्री कर की दर से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि यह 10 प्रतिशत से कम है तो यह उससे अधिक हो सकता है। अधिनियम के उद्देश्य और अंतर-राज्यीय बिक्री कर की चोरी को रोकने के लिए विधायिका की चिंता को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान को वैध माना गया था। हालांकि, खन्ना ने अपने विस्तृत फैसले में अदालत की ओर से बोलते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि विधायिका को नियमों या अधिसूचनाओं द्वारा कानून बनाने की कार्यपालिका को शक्ति प्रदान करते समय किसी भी नीति, सिद्धांत या मानक का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय के पैरा 12 में कानून स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया गया था: -

"हम खुद को इस विचार से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं, जिसे बहस के दौरान प्रचारित किया गया है कि यदि कोई विधायिका किसी प्रतिनिधि को अधीनस्थ या सहायक कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, तो विधायिका को किसी भी नीति, सिद्धांत या मानक का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जो उस शक्ति के प्रयोग में प्रतिनिधि के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सके।

इसने इस बात पर भी जोर दिया कि विधायी अधिकार का अत्यधिक प्रत्यायोजन लोगों की संप्रभुता का उल्लंघन था। यह देखा गया, -

"विधायी अधिकार के अत्यधिक प्रत्यायोजन के खिलाफ नियम लोगों की संप्रभुता का एक आवश्यक आधार है। नियम में कहा गया है कि विधायी नीति के मामले में प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं है।

प्रिंसिपल एक्ट, 14 नवंबर, 1957 को प्रकाशित। इस शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 7-ए (4) के तहत उक्त अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार को धारा 7-ए (4) के तहत प्रदान की गई थी। मुख्य आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग एक अधिसूचना प्रकाशित करके किया जा सकता है और धारा 7-ए (5) के तहत यह संलग्न किया गया था कि ऐसी अधिसूचना को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए; 14 दिनों की अवधि "जितनी जल्दी हो सके"। पुनर्गठन अधिनियम के बाद, चंडीगढ़ पंजाब राज्य का हिस्सा बनना बंद कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और प्रशासन का प्रमुख मुख्य आयुक्त था। इस प्रकार, 1966 के बाद, दूसरे सेचेडुले को शामिल करने या हटाने की शक्ति केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त में निहित थी। दूसरी अनुसूची में संलग्न है; प्रिंसिपल एक्ट में, पंजाब की तत्कालीन विधायिका ने धारा 93 से शुरू होने वाले नगरपालिका अधिनियम के कुछ प्रावधानों को शामिल किया। उनके अवलोकन से पता चलता है कि ये प्रावधान फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, जल आपूर्त, स्वच्छता की स्थिति, नालियों, पाइपों बिछाने, सीवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अव्यवस्थित व्यक्तियों को हटाने, भवनों के निरीक्षण और उनके निर्माण आदि से संबंधित हैं। धारा 61 से 86 में निहित कराधान और उसके लिए प्रदान की गई मशीनरी के संबंध में प्रावधान उक्त अनुसूची में शामिल नहीं किए गए थे। धारा 4 से 10 में निहित नगरपालिका के गठन के बारे में प्रावधान, धारा 51 और 52 में निहित नगरपालिका निधि के गठन के साथ-साथ धारा 56 के तहत प्रावधान जो नगरपालिका में निहित संपत्ति से संबंधित थे, को भी इस अनुसूची से हटा दिया गया था। जहां तक विवाद

का संबंध है, नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 सबसे महत्वपूर्ण है। यह इस प्रावधान में है कि नीति; भवन आदि के मालिकों पर कर लगाना, या दूसरे शब्दों में गृह कर लगाना विधायिका का अधिकार सन्निहित है। इस प्रावधान में यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी नगरपालिका समिति अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समय-समय पर हाउस टैक्स लगा सकती है, जो अनकल के अधीन है कि ऐसा कर उसमें निर्धारित अधिकतम दर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि नगरपालिका समिति ऐसा कर लगाना चाहती थी, तो धारा 62 से प्रावधानों में मशीनरी प्रदान की गई थी। इस मशीनरी में गृहकर लगाने के लिए एक विशेष बैठक में समिति द्वारा एक प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है, जिसमें जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं और राज्य सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके बाद, समिति को संपत्तियों के मूल्यांकन के बारे में एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करना है।



कर की वास्तविक राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रत्येक मालिक या कब्जेदार, संबंधित व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के बाद मूल्यांकन सूची तैयार करना, और अंतिम मूल्यांकन सूची। पीड़ित व्यक्तियों द्वारा अपील दायर करने के संबंध में मशीनरी भी प्रदान की गई है। इन प्रावधानों को मुख्य आयुक्त द्वारा 10 जुलाई, 1968 को एक अधिसूचना प्रकाशित करके प्रधान अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करके चंडीगढ़ शहर के क्षेत्र में लागू किया गया था। 1957 से जब संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत दूसरी अनुसूची जिसमें नगरपालिका अधिनियम के कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया था, को प्राथमिक अधिनियम में जोड़ा गया था, पंजाब सरकार ने 1966 तक, यानी पुनर्गठन की तारीख तक और उसके बाद, मुख्य आयुक्त ने उक्त दूसरी अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को शामिल करने का आवश्यक नहीं समझा। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार 1959 में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा 'नीतिगत निर्णय' के रूप में घोषणा की कि चंडीगढ़ शहर में 25 साल तक हाउस टैक्स सहित कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हमारे यहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकार में शामिल दल के पास विधायिका में बहुमत होता है और इस प्रकार सरकार का निर्णय नीति के मामलों में विधायिका के निर्णय का प्रतीक होता है। तथ्य यह है कि सरकार द्वारा चंडीगढ़ में कर न लगाने के निर्णय की किसी भी समय विधायिका द्वारा आलोचना या असहमति या असहमति व्यक्त नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्धारण करने के लिए बुलाया गया है कि क्या तत्कालीन पंजाब विधायिका ने 1957 में संशोधन अधिनियम अधिनियमित करके अपनी मंशा और नीति स्पष्ट कर दी थी कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 में सन्निहित गृह कर कार्यपालिका द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वह मुख्य प्रशासक हो या मुख्य आयुक्त। यदि विधायिका ने संशोधन अधिनियम लागू करते समय अपना मन बना लिया था कि हाउस टैक्स लगाया जाना चाहिए और केवल विवरण कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए, तो दूसरी अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम की कम से कम धारा 61 और 62 को शामिल करके अपनी इच्छा और इरादे को व्यक्त करने में विधायिका के रास्ते में कुछ भी नहीं आता है। गैर-समावेशन कर से संबंधित इन दो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से कोई संदेह नहीं है कि तत्कालीन विधायिका ने चंडीगढ़ में, जो एक नया विकासशील शहर था, नीतिगत मामले के रूप में गृह कर लगाने के संबंध में अपनी गंभीरता या उपयुक्तता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। केवल तथ्य यह है कि प्रधान अधिनियम की धारा 7-ए (4) के तहत राज्य सरकार को शक्ति दी गई थी और पुनर्गठन के बाद 1 मुख्य आयुक्त को शामिल करने की शक्ति दी गई थी

नगरपालिका अधिनियम के किसी भी प्रावधान को दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधान अधिनियम की धारा 7-ए के तहत कार्यपालिका और उसी के प्रयोग में आक्षेपित अधिसूचना अनुबंध पी 1 जारी करना, सशर्त कानून का मामला था न कि प्रत्यायोजित कानून। इस प्रकार विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन का प्रश्न अप्रासंगिक था। सशर्त कानून को किसी भी आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। *इंदर सिंह के मामले* (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात के अनुसार, "सशर्त कानून" का अर्थ है कि कानून अपने सभी विवरणों में विधायिका द्वारा इंगित किया जाता है, लेकिन बाहरी प्राधिकरण के पास एकमात्र शक्ति "इसे ऐसे क्षेत्र में या ऐसे समय में लागू करने की है जो वह तय कर सकता है"। वर्तमान मामले में, यह एकमात्र शक्ति नहीं है जिसे कार्यपालिका को प्रत्यायोजित किया गया था। यह सरकार के असीमित और निरंकुश विवेक पर छोड़ दिया गया था, जिसमें धारा 7-ए के तहत दूसरी अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम के किसी भी प्रावधान को शामिल किया गया था, जिसमें कर लगाने से संबंधित प्रावधान और इसे लगाने के तरीके और मशीनरी शामिल हैं। इस तरह की व्यापक शक्तियों के प्रत्यायोजन और उनके प्रयोग को "सशर्त कानून" के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुख्य आयुक्त द्वारा 10 जुलाई, 1966 को जारी की गई अधिसूचना, अनुलग्नक पी. 5, जिसके तहत चंडीगढ़ में गृह कर लगाने से संबंधित नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 और अन्य प्रावधानों को दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था, स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह आवश्यक विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त है। इसके बाद 31 जुलाई, 1968 को मुख्य प्रशासक द्वारा जारी अधिसूचना, अनुबंध पी. 6, जिसके द्वारा मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ चंडीगढ़ शहर में इन प्रावधानों को लागू किया गया था, एक परिणामी उपाय था, को भी रद्द किया जाना चाहिए।



41. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी जोरदार तर्क दिया गया था कि भले ही उपरोक्त अधिसूचनाएं, अनुलग्नक पी. 5 और पी. 6 क्षेत्र को वैध और ऑपरेटिव मानते हैं, फिर भी हाउस टैक्स की लेवी को बनाए नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 के तहत, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि इस तरह का कर "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम द्वारा निर्देशित तरीके से" लगाया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि इस प्रकार संदर्भित उद्देश्यों को नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 और 52 में सन्निहित किया गया था, जिसके अनुसार "प्रत्येक नगर पालिका" के लिए एक नगरपालिका निधि बनाना अनिवार्य था, जिसमें नगरपालिका समिति द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व को जमा किया जाना था। धारा 52(1) और (2) में विस्तार से यह निर्धारित किया गया है कि इस निधि का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। वहीं

नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका निधि के गठन से पहले "नगर पालिका" का गठन किया जाना था। ऐसी नगरपालिका के गठन के लिए जारी की गई किसी भी अधिसूचना को स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करना था जिससे यह संबंधित है। "नगर पालिका" और नगरपालिका समिति" है। दो अलग-अलग और अलग-अलग अर्थों के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 3 (9) के तहत नगरपालिका का अर्थ है इस (नगरपालिका अधिनियम) द्वारा या उसके तहत घोषित किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका माना जाता है, धारा 3 (4) के तहत "कोमिनिटी" का अर्थ है नगरपालिका समिति। यहां तक कि संविधान भी। ऐसी समिति की स्थापना धारा 11 से आगे में निहित है। वकील के अनुसार, धारा 4 के तहत प्रदान की गई नगरपालिका को अस्तित्व में लाए बिना नगरपालिका निधि नहीं बनाई जा सकती है और नगरपालिका निधि के गठन के बिना, नगरपालिका कर की वसूली को प्रभावी नहीं किया जा सकता है क्योंकि नगर पालिका और नगरपालिका निधि आवश्यक पूर्व-शर्तें थीं, इससे पहले कि गृह कर लगाया जा सके। अधिनियम का उद्देश्य और अधिनियम की धारा 61 के तहत परिकल्पित तरीके को पूरा नहीं किया जा सका। इस बात पर भी जोर दिया गया कि यद्यपि नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 और 52 को एक अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है, फिर भी धारा 4) नगरपालिका अधिनियम को प्रधान अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और इस प्रकार, नगरपालिका अब तक इसमें नहीं आई थी! अस्तित्व। इन दलीलों के जवाब में, चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि अब तक नगरपालिका के गठन के लिए प्रावधान करने वाली धारा 4 को केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं किया गया था, लेकिन मूल अधिनियम में संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल धारा 7-ए (2) पर भरोसा किया गया था। जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने पर, मुख्य प्रशासक चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में, जैसा भी मामला हो, समान शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी अधिसूचना द्वारा लागू प्रावधानों के तहत समान कार्यों का पालन करेगा जैसा कि एक नगरपालिका समिति या उसके अध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी या समिति का कोई अन्य पदाधिकारी प्रयोग करेगा और प्रदर्शन करेगा यदि चंडीगढ़ पहले नगर पालिका थी। क्लास।

हालांकि, इसके बारीकी से अवलोकन से पता चलता है कि इस प्रावधान को लागू करके, चंडीगढ़ के लिए "प्रथम श्रेणी की नगरपालिका" का गठन नहीं किया गया था, न ही यह बताया जा सकता है कि इस प्रावधान को लागू करके, यह नहीं किया गया था

नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 के तहत चंडीगढ़ शहर के लिए एक नगरपालिका का गठन करना आवश्यक है। उपरोक्त प्रावधान केवल मुख्य प्रशासक को नगरपालिका समिति की शक्तियां प्रदान करता है और इस प्रकार, निर्वाचित नगरपालिका के गठन के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम की धारा 11 और 12 का सहारा लेना आवश्यक नहीं था। नगरपालिका अधिनियम की योजना के अनुसार, नगरपालिका समिति चाहे नामित हो या निर्वाचित, एक विधिवत विपक्ष के अस्तित्व का अनुमान लगाती है! मैंने नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 के तहत नगरपालिका का गठन किया। यह विवादित नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में न केवल चंडीगढ़ शहर शामिल है, बल्कि इसके आसपास के कई गांव भी हैं। जब तक नगरपालिका के गठन के उद्देश्य के लिए स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं को नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है और आपत्तियां आमंत्रित करने और उस पर विचार करने के बाद, अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि "नगरपालिका" अस्तित्व में आई थी और प्रशासन के उद्देश्य के लिए इसकी सीमाएं क्या थीं। नगरपालिका अधिनियम के 51, 52 और 61 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। नगरपालिका अधिनियम की योजना के अनुसार, करों या अन्यथा से प्राप्त सभी आय और राजस्व को नगरपालिका निधि में जमा किया जाना है, जिसे नगरपालिका निधि में गठित किया जाना है; संबंधित "नगरपालिका" का नाम। नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 के तहत "नगरपालिका" के रूप में जानी जाने वाली कानूनी इकाई के अस्तित्व में आए बिना, नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 के तहत परिकल्पित कोई नगरपालिका निधि नहीं हो सकती है क्योंकि निधि नगरपालिका के नाम पर होनी चाहिए और इसका उपयोग नगरपालिका अधिनियम की धारा 52 के तहत स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। नगरपालिका और नगरपालिका की अनुपस्थिति में, धारा 61 और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत लगाए और एकत्र किए जा सकने वाले कर का उपयोग करने के लिए मशीनरी के लिए धन का पूरी तरह से अभाव होगा और यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि कर "इस (नगरपालिका) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तर्क को पूरा करने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने 20 सितंबर, 1977 को वित्त सचिव से भारत सरकार को प्राप्त एक पत्र को मेरे ध्यान में लाया, जिसमें कहा गया है, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उन बैंकों में एक अलग खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें इस प्रकार एकत्र किया गया हाउस टैक्स जमा किया जाना था। यह भी बताया गया कि अधिनियम के अनुसरण में मुख्य प्रशासक द्वारा जून, 1977 में पांच बैंकों में गृहकर शीर्षक के तहत एक खाता खोला गया था और एक स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि लागू कर द्वारा प्राप्त गृह कर भारत की समेकित निधि में जमा नहीं किया जाएगा और यह भारत सरकार के राजस्व का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि, यह स्वीकार किया गया था कि 1976 में हाउस टैक्स लगाने से पहले, चंडीगढ़ प्रशासन के पास अपने राजस्व और आय को क्रेडिट करने के लिए कोई अलग फंड नहीं था और पूरा खर्च भारत की समेकित निधि से प्राप्त अनुदान से पूरा किया जाता था जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमति दी गई थी। तथ्य यह है कि भारत सरकार के वित्त सचिव के निर्देशों पर, गृह कर से होने वाली आय से संबंधित एक अलग खाता खोला गया है, कानून के दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव से सहमत होना संभव नहीं है कि (वही प्रक्रिया नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए पर्याप्त थी जैसा कि धारा 4 में निहित है, नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 और 52 और यह कि गृह कर से होने वाली आय भारत की समेकित निधि का हिस्सा नहीं होगी। जब तक भारत सरकार ने पिछली स्थिति को बदलने के लिए औपचारिक और कानूनी रूप से वैध निर्णय नहीं लिया, तब तक चंडीगढ़ पर लागू नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका निधि का गठन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस दलील को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लगाए गए कर से प्राप्त कर की राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा होगी। इसी तरह की परिस्थितियों में, चंडीगढ़ में लगाए गए पेशे कर को इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा *मदन तरलोक सिंह और अन्य के मामले में रद्द कर दिया गया था* । *भारत संघ और अन्य* । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, चंडीगढ़ में गृह कर की वसूली को इस आधार पर भी कायम नहीं रखा जा सकता है।

42. 1977 की रिट याचिका संख्या 2538 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री झिंगन ने निम्नलिखित तर्कों को अपनाते हुए कहा: श्री सिब्बल ने इस आधार पर भी लागू लेवी की वैधता को चुनौती दी है कि हाउस टैक्स नगरपालिका अधिनियम की धारा 63, 64 और 67 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं लगाया गया था। यह तर्क दिया गया था कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 63 के तहत, एक ही समय में पूरे चंडीगढ़ शहर के लिए मूल्यांकन सूची तैयार करना अनिवार्य था और उसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए थीं, लेकिन मूल्यांकन सूचियां तैयार की गई थीं। केवल कुछ क्षेत्रों के लिए। ये था

इस बात पर जोर दिया गया कि सूचियों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी गई थी, धारा 65 के तहत, आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस मुख्य प्रशासक द्वारा दिया जाना चाहिए था, जबकि यह मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था और इस संबंध में मूल्यांकन प्राधिकरण को शक्तियों का प्रत्यायोजन नगरपालिका अधिनियम की धारा 33 के तहत स्वीकार्य नहीं था। धारा 66 के तहत परिकल्पित अब तक कोई अंतिम सूची प्रमाणित नहीं की गई थी और धारा 66 में परिकल्पना की गई थी कि सुनवाई पूरी समिति द्वारा की जानी चाहिए, न कि केवल एक सदस्य द्वारा। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील आनंद स्वरूप के अनुसार, कुछ क्षेत्रों के संबंध में मूल्यांकन सूचियां एक समय में प्रकाशित की गई थीं और बाद में अन्य क्षेत्रों के संबंध में सूचियां प्रकाशित की गईं और सूचियों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। निरीक्षण के अवसर की पूरी अनुमति दी गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि शहर के सभी सेक्टरों की सूची अक्टूबर, 1978 तक प्रकाशित की जा चुकी थी और एक ही समय में पूरे शहर के लिए सूचियों को प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं था। विद्वान वकील के अनुसार, मुख्य प्रशासक समिति के सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम थे और अधिसूचना, अनुबंध बी 3 के अनुसार, नगरपालिका अधिनियम की धारा 66 के तहत अंतिम रूप से तय की गई सूचियों पर समिति के कम से कम दो सदस्यों के हस्ताक्षर से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया था और आकलन प्राधिकरण को कुछ उद्देश्यों के लिए मुख्य प्रशासक की शक्तियां भी प्रदान की गई थीं। अधिसूचना, अनुबंध बी. 1. यह तर्क दिया गया था कि वित्त सचिव को अधिसूचनाओं, अनुबंध बी 6 और बी 7 द्वारा मुख्य प्रशासक की शक्तियां प्रदान की गई थीं और एक उप मुख्य प्रशासक को भी अधिसूचना, अनुबंध बी 2 द्वारा नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क भी खारिज कर दिया गया कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 66 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से हाउस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है और इस संबंध में प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था। मैंने केवल दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान देना उचित समझा है, लेकिन मुख्य विवादों पर मेरे निष्कर्षों के मद्देनजर उस पर कोई >निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित अधिसूचनाओं में कानूनी खामियों को देखते हुए चंडीगढ़ में हाउस टैक्स लगाया गया है। अनुलग्नक पी. 5 और पी. 6 को रद्द किया जाता है।

43. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एस.एस. *सविहावालिया*, - मैं सहमत हूँ।

**एन.के.एस.**

9. जून, 1976 तक, चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में कर लगाने के लिए कोई प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया। 14 जुलाई, 1976 को चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र (असाधारण) में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें

चंडीगढ़ में भूमि और भवनों पर कर लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। उसी के जवाब में, लगभग 295 आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिन्हें चंडीगढ़ के तत्कालीन मुख्य प्रशासक श्री केजे के मुखर्जी ने 24 अगस्त, 1976 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जिसकी एक प्रति अनुबंध पी 9 है। भूमि और भवनों पर कर लगाने को मुख्य प्रशासक द्वारा नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 (एल) (ए) के साथ धारा 62 (10) (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया था, जिसकी एक प्रति 27 अगस्त, 1976 की अधिसूचना के माध्यम से है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी 10 है। इसके बाद, जून, 1977 में आकलन प्राधिकारी द्वारा नगरपालिका अधिनियम की धारा 65 के तहत प्रत्येक याचिकाकर्ता पर हाउस टैक्स की कुछ राशि का प्रस्ताव करते हुए नोटिस जारी किए गए थे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

